

## प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), भारत सरकार का वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो 10 से 65 वर्ष आयु वर्ग के लिए लागू होता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं जैसे बैंक खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और बीमा तक सस्ती पहुंच बनाना है। पेंशन। यह वित्तीय समावेशन अभियान भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। [1] उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस योजना की घोषणा की थी।

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित, इस योजना के तहत उद्घाटन के दिन 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए थे। [2] [3] गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस उपलब्धि को मान्यता देते हुए कहा: "वित्तीय समावेशन अभियान के एक भाग के रूप में एक सप्ताह में खोले गए सबसे अधिक बैंक खाते 18,096,130 हैं और 23 से 29 अगस्त, 2014 तक भारत सरकार द्वारा हासिल किए गए थे।" [4] ] 27 जून 2018 तक, 318 मिलियन से अधिक बैंक खाते खोले गए और इस योजना के तहत, 792 बिलियन (US \$ 12 बिलियन) जमा किए गए। [५]

### लाभ

नो-फ्रिल खाते खोलना: पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती है। छह महीने के बाद ₹ 10,000 (US \$ 140) तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी उपलब्ध है। ब्याज जमा पर है। खाते के लिए मुफ्त RuPay डेबिट कार्ड।

पता-आपके-ग्राहक (केवाईसी) मानदंडों पर छूट: जिन व्यक्तियों के पास वैध पहचान दस्तावेज नहीं है, वे बैंक खाता भी खोल सकते हैं। इस प्रकार का खाता कॉल "स्माल अकाउंट", एक वर्ष के भीतर नियमित किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है। यह सेवा प्राप्त करने के लिए देरी और रिसाव को कम करता है।

बीमा: Acc 200,000 (यूएस \$ 2,900) का आकस्मिक बीमा कवर लाभार्थी की मृत्यु पर देय of 30,000 (यूएस \$ 430) का जीवन कवर प्रदान करता है।

## प्रदर्शन

रन-अप में की गई तैयारियों के कारण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उद्घाटन के दिन, 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा- "आइए आज हम आर्थिक स्वतंत्रता के दिन के रूप में मनाएं।" सितंबर 2014 तक, 30.2 मिलियन खाते बैंक खोले गए]] 2.024 मिलियन खातों के साथ, केनरा बैंक 1.621 मिलियन खाते, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया 1.598 मिलियन खाते और 1.422 मिलियन खातों के साथ बैंक ऑफ़ बड़ौदा। [9] 20 जनवरी 2015 को, इस योजना ने 'सबसे अधिक बैंक खाते एक सप्ताह में खोले' के लिए नए रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया।

जन धन खातों में शेष राशि 9 नवंबर 2016 और 23 नवंबर 2016 के बीच US 270 बिलियन (यूएस \$ 3.9 बिलियन) से अधिक हो गई। 11%] 1.9 मिलियन घरवालों ने मई 2016 तक (2.56 बिलियन (US \$ 37 मिलियन) की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया है। [12] उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को इस योजना के तहत कुल जमा का 29% मिला है, [13] जबकि केरल और गोवा देश के पहले ऐसे राज्य बन गए हैं जो हर घर को एक बुनियादी बैंक खाता प्रदान करते हैं। [१४]

खाताधारकों की कुल संख्या 294.8 मिलियन थी, जिसमें ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के 176.1 मिलियन खाताधारक शामिल थे। अगस्त 2017 तक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) द्वारा कुल 227 मिलियन RuPay कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2017 तक जमा राशि बढ़कर .9 656.97 बिलियन (US \$ 9.5 बिलियन) हो गई। [6]

विभिन्न अध्ययनों के विश्लेषण के अनुसार, "खाते के स्वामित्व और वित्तीय सेवाओं के उपयोग को सक्षम करने से परे, पीएमजेडीवाई ने विभिन्न जनसांख्यिकी के लिए वित्तीय समावेशन की सुविधा भी प्रदान की है। जबकि कार्यक्रम ने वास्तविक वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, यह स्पष्ट है कि नीति में सुधार। कम आय वाले राज्यों में संचार, चौड़ीकरण और गहरी प्रगति, और बैंक-एजेंट मॉडल में किंग को बाहर निकालना महत्वपूर्ण होगा यदि ये कठिन-लाभ लाभ टिकाऊ साबित होने के लिए हैं। "[15] कम से कम 300 मिलियन नए परिवारों को जन मिला है। धन खातों जिसमें लगभग (650 बिलियन (यूएस \$ 9.4 बिलियन) जमा किए गए हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2017 को वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से योजना की तीसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर कहा।

वेबसाइट [www.pmjdy.gov.in](http://www.pmjdy.gov.in)